एक अध्ययन में पता लगा है कि, वन्यजीव अभयारण्य उष्णकटिबंधीय जीवों को हानिकारक मानवीय गतिविधियों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, इन क्षेत्रों में जैगुआर, माउन्टेन गोरिल्ला और सुंडा पैंगोलिन जैसे स्तनपायी जीव इंसानी गतिविधियों से प्रभावित पाए गए हैं। यह स्थिति तब है, जबकि ये जीव नेचर रिज़र्व में बहुत अंदर रहते हैं। नॉर्वेजिअन युनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साईन्सेज़, राइस युनिवर्सिटी एवं वाखनिंगन युनिवर्सिटी एण्ड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने बताया कि, संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को वनों की कटाई के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। मुख्य शोधलेखक असुन्सियॉन सैम्पर -पस्कुअल ने कहा, ''संरक्षित वन के अंदर रहने का अर्थ यह नहीं है कि, ट्रॉपिकल जानवर इंसानी गतिविधियों के प्रभाव से अपने आप ही सुरक्षित हैं। हमारे पास प्रमाण हैं कि, संरक्षित क्षेत्र के अंदर और बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जानवर उससे प्रभावित हो रहे हैं।'' वृहद एवं लम्बे समय तक चले कैमरा ट्रैप वाइल्डलाइफ सर्वेक्षणों से प्राप्त तस्वीरों का शोधकर्ताओं ने अध्ययन कर यह पता लगाया कि, मानव गतिविधियों का, ट्रॉपिकल क्षेत्रों के 16 संरक्षित वनों में स्तनपायी जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ा है। संरक्षित वन, जहाँ कैमरा ट्रैप लगाए गए उनमें अफ्रीका का, चित्र में नज़र आ रहा, बविन्डी इम्पैनिट्रेबल नैशनल पार्क, साउथ अमेरिका का जसुनी नैशनल पार्क और दक्षिण पूर्व एशिया का पज़ा फॉरैस्ट रिज़र्व प्रमुख हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि, जंगलों की कटाई के कारण हुए वनों के विखंडन का कुछ जानवरों पर खासतौर पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, पर कुछ प्रजातियाँ, जो खास तरह के आवास में ही रहती हैं, वे वनों के विखंडन के कारण पनपी भी हैं। पस्कुअल ने कहा, ''जिस तरह से नए-नए संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से यह सोचने की ज़रुरत है कि, संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व बाहर कौन से ऐसे कारक हैं जो बायोडायवर्सिटी को प्रभावित कर रहे हैं।''

मध्यप्रदेश में ''नो सी.एम. फेस चेंज'' पॉलिसी पर मुहर लगाई अमित शाह ने

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार रात को भोपाल में एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि, मुख्यमंत्री चेहरा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दोनों ही नहीं बदले जायेंगे

भोपाल,12 जुलाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई थीं। इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया गया कि चुनाव से पहले राज्य में बड़े बदलाव हो सकते हैं, खास तौर से जहां भाजपा की स्थिति कुछ कमजोर मानी जा रही है। इन कयासों के बीच मंगलवार रात को भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। मीटिंग में शाह ने साफ कर दिया कि न तो मुख्यमंत्री चेहरा और न ही बीजेपी चीफ बदला जाएगा। कहा जा रहा है कि शाह अचानक ही मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। सोमवार तक मुख्यमंत्री समेत चुनावी राज्य के शीर्ष नेताओं को भी उनके आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

अमित शाह की बैठक में शामिल हुए कई नेता मध्य प्रदेश बीजेपी के अलग-अलग शक्ति केंद्र माने जाते हैं। हालांकि, मीटिंग के दौरान शाह ने सरल संदेश दिया कि पार्टी को यूनिट के रूप में आक्रामक तरीके से लड़ना होगा। साथ ही चुनाव की तैयारी में उनकी भागीदारी की समीक्षा दैनिक आधार पर की जाएगी। बैठक में मौजूद बीजेपी नेता ने बताया, अमित भाई ने साफ शब्दों में कहा कि सीएम चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष ही रहेंगे। सभी को इसका पालन करने को भी कहा गया है।

> **जैसा कि विदित है कि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई थीं। इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि, चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव हो सकते हैं।**

रिपोर्ट के मुताबिक, शाह ने शिकायत की कि राज्य में नेतृत्व को लेकर यहां बैठे लोग अलग-अलग आवाज में बोल रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश इकाई के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि इसे अभी रोकने की जरूरत है। शाह इस बात से भी नाखुश बताए गए कि भाजपा अपने अभियान में आक्रामक नहीं है। उन्होंने विजय संकल्प अभियान की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। राज्य में चुनाव से पहले भाजपा की ओर से की जाने वाली इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। शाह ने मध्य प्रदेश यूनिट से इस कार्यक्रम पर फोकस करने को कहा है। वह इसे आगे बढ़ाने के लिए जुलाई के आखिर में राज्य में वापस आ सकते हैं।

भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले शाह ने चुनाव की तैयारियों की गहन समीक्षा करने के बाद मध्य प्रदेश से विजय संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की है। शाह ने बैठक में मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की और चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। शर्मा ने कहा कि उन्होंने चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लिया और विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया। बैठक में मध्य प्रदेश के लिए भाजपा प्रभारी नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव व उनके कैबिनेट सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश और मप्र-छत्तीसगढ़ प्रभारी अजय जम्वाल भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, सिंधिया, तोमर, पटेल और राज्य कैबिनेट मंत्रियों ने हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया। बैठक के बाद शाह पार्टी कार्यालय से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल

जयपुर, 12 जुलाई (का.सं.)। शुक्रवार14 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सुबह 11 बजे विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी दोपहर 1 बजे सीकर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

> **यह बैठक 14 जुलाई से शुरु हो रहे विधानसभा सत्र के संदर्भ में बुलाई गई है।**

'चित मैं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गई थी। लोकसभा के चुनाव परिणामों से भाजपा को कोई खास लेना-देना नहीं है क्योंकि वह वाय.एस.आर.सी.पी. के समर्थन के विषय में आश्वस्त है। अगर तेलुगू देशम जीतती है तो सत्तारूढ़ भाजपा को सीधा लाभ होगा। दरअसल, इस बार भाजपा हिन्दी भाषी क्षेत्र, महाराष्ट्र एवं बिहार में अपने प्रतिकूल स्थिति मानकर चल रही है। पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से पंचायत चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है, उसे देखते हुये, वहाँ भी भाजपा के लिए 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहरा पाना मुश्किल हो सकता है।

ममता बनर्जी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले राजनैतिक गुटों ने जो हिंसा की राजनीति आरंभ की थी उसे ममता और ऊंचे स्तर तक ले गई है। अगर ये चुनाव केन्द्रीय सुरक्षा बलों या सेना के नियंत्रण में होते तो तस्वीर अलग हो सकती थी। बंगाल में विपक्ष के नेता ने कहा था कि भाजपा जंगल महल और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जीती क्योंकि यहां मतदान में भारी फर्जीवाड़ा हुआ और आम आदमी को तो वोट डालने ही नहीं दिया गया।

भारतीय चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनावी गड़बड़ियों एवं आरोपों का मुद्दा उठाया

कोलंबिया में आयोजित इस बैठक में 119 देशों के चुनाव आयोगों ने भारत की बात का समर्थन किया और कहा, ''हम भी इस दंश का शिकार हैं तथा लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पर लांछन लगाने का बढ़ता रवैया चिंता का विषय है''

कोलंबिया/नई दिल्ली, 12 जुलाई। चुनावी नतीजों के आने के बाद चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोगों के खिलाफ जिस तरह से झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाने का ट्रेंड बढ़ा है,उससे अकेले भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं।

भारत के चुनाव आयोग ने वैश्विक स्तर पर यह मुद्दा ऐसे समय पर उठाया है, जब अमेरिका, ब्राजील और हाल ही में तुर्की के चुनाव में गड़बड़ियों का मुद्दा काफी गरम रहा है।

खासकर इससे चुनावी विश्वसनीयता के प्रभावित होने का बड़ा खतरा है। भारत निर्वाचन आयोग ने फिलहाल इस दिशा में उठाए गए अहम कदमों के साथ ही अब दुनिया के दूसरे देशों को भी इस खतरे को लेकर सतर्क किया है।

साथ ही कहा है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। बाद में जिसका काफी देशों ने समर्थन भी किया है। कोलंबिया में चल रही एसोसिएशन आफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में इस मुद्दे को दुनिया के कई देशों ने प्रमुखता से रखा और अपनी चिंताएं जताई। इस संगठन के मौजूदा समय में दुनिया के करीब 119 देशों के चुनावी प्रबंधन निकाय इसके सदस्य है।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग भी इस बैठक में शामिल है। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनावी विश्वसनीयता का संकट इस समय पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। खासकर जिस तरह चुनाव के दौरान या बाद में आयोग के काम-काज को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए जाते है, वह काफी गंभीर विषय है।

चुनाव आयोग खुद भी ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) को लेकर ऐसे ढेरों आरोपों से जूझ चुका है। हालांकि, आयोग ने इससे निपटने के कई अहम कदम उठाए है, उनमें से पहला पारदर्शिता के स्तर को बेहतर रखना और दूसरा झूठे व तथ्यहीन आरोपों को सख्ती से निपटना है।

वहीं, इस झूठ को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया है।

ऐसे में आयोग ने सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने के लिए अब एक अलग सेल गठित किया है, जो 24 घंटे चुनाव से जुड़े किसी भी विषय पर नजर रखता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की उन टिप्पणियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है।

एकल पट्टा प्रकरण से सी.बी.आई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुमति दे दी है। जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश रामशरण सिंह की याचिका में उनके पुत्र सुरेन्द्र सिंह की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने वाले अशोक पाठक को कहा है कि वह चाहे तो नए सिरे से सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं। प्रकरण में पूर्व में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस जीएस संधू, आरएएस ओंकार मल सैनी व निष्काम दिवाकर सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था। हालांकि हाईकोर्ट पूर्व में शांति धारीवाल के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई को रद्द कर चुका है। वहीं तीनों पूर्व अधिकारियों के खिलाफ लंबित मुकदमे को वापस लेने की अनुमति भी दी जा चुकी है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रामशरण सिंह की ओर से उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रामशरण सिंह का देहांत हो चुका है। वे मामले की सुनवाई आगे नहीं चाहते थे और वह भी प्रकरण में आगे कार्रवाई नहीं चाहता। इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में पूर्व में दायर इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

वहीं अशोक पाठक की ओर से अधिवक्ता संदीप खंडेलवाल ने कहा कि मामले में मिलीभगत से ऐसा किया जा रहा है। रामशरण सिंह ने मुकदमे के लिए सैशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लडाई लडी है। वहीं भ्रष्टाचार का अपराध समाज के प्रति होता है। यह संपत्ति को लेकर कोई वाद नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के बेटे को केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा मामले में सीबीआई भी अपना जवाब पेश कर चुकी है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका वापस लेने का प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया।

मामले के अनुसार एसीबी ने वर्ष 2014 में परिवादी रामशरण सिंह की गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली की शिकायत को लेकर मामला दर्ज किया था। एसीबी ने मामले में कंपनी के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू, जेडीए जोन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर और गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों अनिल अग्रवाल व विजय मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट 15 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर एसीबी में दर्ज एफआईआर और निचली अदालत की कार्रवाई को शांति धारीवाल की हद तक रद्द कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने संधू सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दे दी थी।

'डिज़ाइन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जायेगा। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के तहत ही चुनाव में उतरेगी। लेकिन अशोक गहलोत को यह बात कौन समझाये। उनके लिये तो दुनिया उन्हीं से शुरु और उन्हीं पर खत्म होती है। हो सकता है कि ''डिज़ाइन बॉक्स'' के काम को रोक देने तथा फिलहाल उसे जारी न रखने के लिये कहने के पीछे यही कारण रहा हो।

राहुल गांधी के केस मे सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (वार्ता)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी ने उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दायर की है। मोदी की मानहानि की शिकायत के बाद अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया था। इसकी वजह से कांग्रेसी नेता की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। गांधी ने निचली अदालत के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। वायनाड लोकसभा के पूर्व सांसद गांधी उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा विधायक ने शीर्ष अदालत में कैविएट दायर कर गुहार लगाई है कि यदि गांधी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हैं तो सुनवाई करते समय उनका (शिकायत करने वाले) पक्ष भी सुना जाए।

> **गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कैविएट दायर की है।**

गौरतलब है कि मानहानि का यह मामला 2019 का है। इस मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गांधी को मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया था।

मोदी आज फ्रांस और यू.ए.ई की यात्रा पर रवाना होंगे

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार सुबह फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की तीन दिन की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे और इस दौरान वह पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की परेड में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। फ्रांस यात्रा के दौरान भारत-फ्रांस रणनीतिक साझीदारी नयी ऊंचाई पर ले जाने के वास्ते लड़ाकू विमानों के इंजन के सहनिर्माण सहित कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को प्रधानमंत्री की यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी गुरुवार सुबह यात्रा पर रवाना होंगे और इस यात्रा के पहले चरण में अपराह्न साढ़े 12 बजे (भारतीय समयानुसार चार बजे) पेरिस पहुंचेंगे। वह सबसे पहले फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष और फिर उस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।

'केन्द्र ने नौ सालों में विज्ञापनों पर 2,330 करोड़ रुपये लुटाये हैं'

युवा कांग्रेस के आर.टी.आई. विभाग के उपाध्यक्ष एडवोकेट आनंद मिश्रा ने ''राइट टू इन्फॉर्मेशन'' के तहत यह जानकारी उजागर की है

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (वार्ता)। युवा कांग्रेस ने कहा है कि, मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्ष में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2330 करोड़ रुपए के विज्ञापन देकर अपने प्रचार प्रसार में जमकर सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. के नेतृत्व में गठित आरटीआई विभाग के उपाध्यक्ष एडवोकेट आनंद मिश्रा ने सूचना के अधिकार-आरटीआई के तहत यह जानकारी हासिल की है। मोदी सरकार ने इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देकर जमकर सरकारी पैसा लुटवाया है।

सूचना के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रिंट मीडिया में 103 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं और नौ साल में यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंचता है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पिछले वित्त वर्ष में 48 करोड रुपए से ज्यादा के विज्ञापन टीवी न्यूज चैनलों को दिए गए जबकि नौ वर्षों का आंकड़ा 1330 करोड रुपए हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट विज्ञापनों एसएमएस, डीसीएटी, डीएड और मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम पर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए हैं।

श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ सरकारी खजाने को विज्ञापनों पर लुटाया जा रहा है वहीं आम जनता महंगाई से त्रस्त है और जरूरत की हर वस्तु आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। हर चीज के भाव आसमान को छू रहे हैं। टमाटर 250 रुपए किलो तक बिक रहा है लेकिन सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है।

कांग्रेस ने वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग-पीएमएलए के दायरे में लाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि सरकार को बताना चाहिए कि उसे यह कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी के साथ पीएमएलए को जोड़कर मोदी सरकार एक साथ दो निशाने साधना चाहती है।

सोनिया गांधी भी विपक्ष...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनके साथ एक ही मंच पर नज़र आएंगी। ममता की तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में भाजपा को हराकर बाजी मार ली और वाम-कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि सोमवार की बैठक में आठ नई पार्टियाँ शामिल होंगी। इन 24 विपक्षी पार्टियों के पास इस समय 150 सांसद हैं और वे अपना आधार बढ़ाने के प्रयास में है।

इनमें शामिल है- मारूमालास्वी द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (एम.डी.एम.के.), कोंगू देसा मक्कल काची (के.डी.एम.के.), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आई.यू.एम. एल.), केरल कांग्रेस (जोसेफ) और केरल कांग्रेस (मणि)।

के.डी.एम.के. और एम.डी.एम.के. 2014 के चुनाव में भाजपा के साथ थीं, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए। सूत्रों ने कहा कि बैठक में तीन कार्य समूह विपक्षी गठबंधन का ढांचा और नाम तैयार करेंगे और एक साझा एजेंडा, राज्य स्तरीय गठबंधन की बारीकियां और विपक्ष की संयुक्त रैलियों के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण भेजे हैं, जिसमें उन्होंने पटना में हुई पहली बैठक की सफलता का उल्लेख किया है। खड़गे ने अपने पत्र में कहा, ''वह बैठक बहुत सफल रही, क्योंकि हम लोगों ने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हो रहे हैं और एकमत से आम चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।''

> **पटना की बैठक पर, केजरीवाल की हठधर्मिता भी छायी थी, तथा शरद पवार व ममता बनर्जी के हस्तक्षेप से केजरीवाल पर नियंत्रण किया गया था।**

उन्होंने लिखा, ''मैं मानता हूं कि इन चर्चाओं को जारी रखना और जो गतिशीलता हमने बनाई है उसे जारी रखना आवश्यक है। हमें देश के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान मिलकर निकालने हैं।'' बीमार चल रहे आर.जे.डी. (राष्ट्रीय जनता दल) प्रमुख लालू यादव ने कहा कि वे बैठक में भाग लेने बैंगलुरु जाएंगे।

पहली बैठक पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव का साया पड़ा जिसमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से दिल्ली संबंधी केन्द्र की अधिसूचना पर कांग्रेस का समर्थन मांगा और इसके अभाव में अगली बैठक का बहिष्कार करने की बात कही थी।

ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेताओं ने दखल देकर इसे बढ़ने से रोका क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से आमने-सामने हो गए थे।

यह बैठक 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र से दो दिन पहले होगी जहां विपक्ष और भाजपा आमने-सामने होंगे।

भाजपा नेता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुलदीप और उसके साथी विजयपाल पर उस समय हमला किया गया जब उन्हें जयपुर से भरतपुर कोर्ट में पेश करने के लिए रोडवेज बस में ले जाया जा रहा था।

आरोपी कुलदीप जघीना और विजय पाल को हथियारबंद चालानी गार्डो की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रोडवेज की बस से भरतपुर लाया जा रहा था, लेकिन टोल प्लाज़ा पर बस के अंदर घुसे बदमाशों ने चालानी गार्ड्स की आंखों के मिर्च पाउडर झोंककर करीब 15 राउंड फायर कर कुलदीप की हत्या कर दी। उस गोलीबारी में बस में सवार दो अन्य यात्री भी घायल हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अज्ञात बदमाश 3 बाइको व दो कारो में सवार थे। देर शाम तक चार आरोपी विष्णु, सौरभ, धर्मराज और बबलू को हिरासत में लिया गया। भरतपुर में 10 महीने पहले 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता कृपाल जघीना की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक, हत्या जमीन एवं प्रोपर्टी विवाद के चलते की गई थी। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि आमोली टोल प्लाजा पर 7 से 8 बदमाशों ने बस के आगे गाड़ी लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए घटना को अंजाम दिया। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई।

गैर आर.ए.एस. से आई.ए.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को दो सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने मामले में गैर आर.ए.एस. अधिकारी एसोसिएशन को मध्यस्थ बनने की अनुमति दे दी है। पहले यह ऐसोसिएशन मामले में पार्टी बनना चाहती थी। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम तय करने की विशिष्ट परिस्थितियों के ब्यौरे सहित अपना जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय और मांगा। इस पर अदालत ने 31 जुलाई तक का समय देते हुए पूर्व में लगाई रोक को उस अवधि तक बढ़ा दिया।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने याचिका में कहा है कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट व उसके नियम-विनियम के तहत उच्चस्तर के 66.67 प्रतिशत पद सीधी आई.ए.एस. भर्ती से और 33.33 प्रतिशत राज्य के प्रशासनिक अफसरों की पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। वहीं विशेष परिस्थिति में ही इस 33.33 प्रतिशत कोटा में से ज्यादा से ज्यादा 15 प्रतिशत पद अन्य सेवा के अफसरों से भरे जा सकते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से हर साल ही अन्य सेवा के अफसरों को आई.ए.एस. पद पर प्रमोशन देने की परंपरा बना ली है। पूर्व में गैर आर.ए.एस. से पदोन्नत हुए आई.ए.एस. का पद खाली होने पर राज्य सरकार इस पद को गैर आर.ए.एस. को ही पदोन्नत कर भरती है।

> **राजस्थान हाई कोर्ट ने गैर आर.ए.एस. को आई.ए.एस. पद पर प्रमोट करने पर लगी रोक 31 जुलाई तक बढ़ा दी है और राज्य सरकार को तब तक जवाब पेश करने को कहा है।**

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 17 फरवरी को सभी विभागों में पत्र भेजकर अन्य सेवाओं से आई.ए.एस. सेवा में पदोन्नति के लिए आवेदन मांगे और स्क्रीनिंग कमेटी ने अन्य सेवा के अफसरों का चयन कर प्रमोशन के लिए यूपीएससी को अपनी सिफारिश भेज दी है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हर बार अन्य सेवा के अधिकारियों को आई.ए.एस. पद पर पदोन्नति देना नियमानुसार सही नहीं है, क्योंकि अपवादिक परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकते हैं। अपवाद कभी भी नियमित भर्ती का तरीका नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार ने खुद ही यह मान लिया है कि आई.ए.एस. पदोन्नति में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का भी एक कोटा है। जबकि यह सिर्फ अपवादिक परिस्थितियों में ही हो सकता है। राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर गैर आर.ए.एस. की पदोन्नति के लिए कोटा तय नहीं कर सकती। ऐसा करना ना केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए तय किए गए पदोन्नति के पदों पर भी अतिक्रमण है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 7 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर गैर आर.ए.एस. को आई.ए.एस. में पदोन्नत करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अदालत ने मामले में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से नाम तय करने का ब्यौरा भी मांगा था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908